



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, शनिवार, 30 सितम्बर, 2006 / 8 आश्विन, 1928

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 30 सितम्बर, 2006

संख्या एल०एल०आर०-डी०(6)-21/2006-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यापाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 28-09-2006 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश मूल्य

परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 17) को वर्ष 2006 के अधिनियम संख्यांक 17 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्तांतरिक्षमा

(सुरेन्द्र सिंह राकुर)

प्रधान सचिव (विधि)।

2006 का अधिनियम संख्यांक 17.

## हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2006

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 28 सितम्बर, 2006 को यथाजनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का 12) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर संक्षिप्त नाम (संशोधन) अधिनियम, 2006 है ।  
और प्रारम्भ ।
- (2) यह 27 मई, 2006 को प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

- 2005 का 12 2. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 28 की उप-धारा 28 का (1) में, विद्यमान प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, संशोधन ।  
अर्थात् :—

“परन्तु धारा 12 की उप-धारा (4) के अधीन आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की किसी अतिरिक्त रकम के प्रतिदाय के लिए आवेदन वर्ष की एक तिमाही के अवसान के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा किया जा सकेगा और जहाँ निर्धारण प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि कर अवधि की विवरणियां सही और पूर्ण हैं, तो वह विहित रीति में ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की अतिरिक्त रकम का प्रतिदाय करेगा या आगामी कर अवधि के लिए उसका अग्रनयन अनुज्ञात करेगा :

परन्तु यह और कि जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी के विरुद्ध कोई अन्वेषण, संवीक्षण, निरीक्षण या लेखापरीक्षा या अन्य कोई जांच लम्बित है और प्रतिदाय मंजूर करने वाले प्राधिकृत अधिकारी की यह राय है कि ऐसे प्रतिदाय के संदाय से ऐसे राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, जो ऐसे अन्वेषण, संवीक्षण, निरीक्षण या लेखापरीक्षा या अन्य जांच की समाप्ति पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से देय हो सकेगा, तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को प्रतिदत्त की जाने वाली रकम के बराबर की प्रतिभूति प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन, या तो अतिरिक्त आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की रकम का प्रतिदाय कर सकेगा या प्रतिदाय को कार्यवाहियों की समाप्ति तक रोक सकेगा :”।

- 2006 के 3. (1) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2006 का  
अध्यादेश एतद्वारा निरसन किया जाता है।
- संख्यांक 2 का निरसन (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की  
और गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्त्वानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी  
व्यावृत्तियां। जाएगी।

**THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2006**

(As Assented to by the Governor on 28th September, 2006)

AN

ACT

*further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).*

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows: —

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2006. Short title and commencement.

(2) It shall and shall always be deemed to have come into force on 27<sup>th</sup> day of May, 2006.

12 of 2005.

2. In section 28 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, in sub-section (1), for the existing first proviso, the following provisos shall be substituted, namely: Amendment of section 28.

“Provided that an application for refund of any excess amount of input tax credit under sub-section (4) of section 12, may be made by a registered dealer after the expiry of a quarter of the year and where the Assessing Authority finds that the returns for the tax period are correct and complete, it shall in the prescribed manner, refund to such registered dealer the excess amount of input tax credit or allow it to be carried forward to the next tax period:

Provided further that where any investigation, scrutiny, inspection or audit or other enquiry is pending against the registered dealer, and the officer authorised to sanction the refund is of the opinion that the payment of such refund is likely to adversely affect the revenue which may become due from such registered dealer at the conclusion of such investigation, scrutiny, inspection or audit or other enquiry, he may, for the reasons to be recorded in writing, either refund the amount of excess input tax credit subject to furnishing of a security equal to the amount to be refunded to such registered dealer or withhold the refund till such time the proceedings are concluded.”.

3. (1) The Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2006 is hereby repealed. Repeal of Ordinance No. 2 of 2006 and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

